दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार 15 अक्टूबर 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 19

महत्वपूर्ण एवं खास

बिना सर्जन के हुआ ऑपरेशन, बेची जा रही थी प्रतिबंधित दवाएं; मेडिकल शॉप के साथ अस्पताल भी हुआ सील

बिजनौर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक निजी अस्पताल में योग्य और अधिकृत सर्जनों के बिना सर्जरी करते पाया गया है। परिसर में बिना लाइसेंस की मेडिकल दुकान से प्रतिबंधित दवाएं भी बेची जा रही थीं। छापेमारी के दौरान विसंगतियां सामने आईं और अस्पताल के साथ-साथ मेडिकल शॉप को भी सील कर दिया गया है। इसके स्टाफ और अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एसडीएम मोहित कुमार ने बताया कि अवैध अस्पताल परिसर में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इसके अलावा, कोई फायर एनओसी नहीं था। ईटीपी के लिए एक प्रमाण पत्र मिला, लेकिन कोई संयंत्र मौजूद नहीं था। इसलिए, अस्पताल को सील कर दिया गया और उसके कर्मचारियों और मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पांच महिलाओं समेत अस्पताल में स्वस्थ हो रहे मरीजों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवीदास ने कहा, अवैध चिकित्सा गतिविधियों को रोकने के लिए अब इस तरह के और छापे मारे जाएंगे।

आज ईसी की पीसी, हिमाचल-गुजरात की चुनाव तारीखों का हो सकता है ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि आयोग इस दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। 182 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 111 विधायक भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म होगा। 68 सीटों वाली इस विधानसभा में भाजपा के पास 45 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 20 एमएलए हैं।

अस्पताल में चिकित्सक से मारपीट, पुलिस जांच में जुटी

रीवा (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के रीवा जिला मुख्यालय स्थित संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में एक चिकित्सक से मारपीट के मामले में पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीती देर रात्रि सतना जिले के मैहर में हुयी एक दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इसी बीच मरीज के साथ आए लोगों ने चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए झूमाझटकी शुरू कर दी और इसके बाद चिकित्सक से मारपीट की। चिकित्सक की शिकायत पर शहर की अमहिया थाना पुलिस ने दो नामजद सहित अन्य आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आज सुबह तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुयी है।

कर्नाटक में भारी बारिश से 13 की मौत

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक में बारिश के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य में और बारिश की भविष्यवाणी की है। बारिश से फसलों और पशुओं को भी भारी नुकसान हुआ है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 1 अक्टूबर से अब तक 28 मवेशियों की मौत हो चुकी है, 3,309 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 6,279 हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है।

आईएमडी के अनुसार, शुक्रवार को बेंगलुरु में औसत से भारी बारिश होगी।

इस बीच, तटीय जिलों के साथ-साथ राज्य के उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, बीदर, धारवाड़, गडग, हावेरी, कलबुर्गी, रायचूर, यादगीर, बल्लारी, चामराजनगर, चिकमगलुरु, बेंगलुरु शहर, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हासन, कोडागु और शिवमोग्गा जिलों में शनिवार को भारी बारिश होगी।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जिला कलेक्टरों को बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और राहत के उपाय करने को कहा है।

'भोजन उपलब्ध कराने के लिए जोमेटो सेवा नहीं चला रहे', बाढ़ पीड़ितों से बोले डीएम

अम्बेडकर नगर (आरएनएस)। जिलाधिकारी ने यहां जिले में बाढ़ पीड़ितों से कहा कि सरकार हर किसी के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए जोमैटो सेवा नहीं चला रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्र से आए राहत शिविर में ठहरे लोगों से कहा, यहां रहने की व्यवस्था है। हम आपको क्लोरीन की गोलियां देंगे। अगर आप किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, डॉक्टर आएंगे और आपको यहां देखेंगे। बाढ़ राहत शिविर का यही उद्देश्य है। साथ ही उन्हें यह भी कहते हुए देखा जा सकता है कि अगर आप घर पर रह रहे हैं तो हम आपको खाना नहीं भेज सकते। सरकार जोमैटो सेवा नहीं चला रही है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल ने लोगों से यह भी कहा कि, 500 मीटर या एक किलोमीटर के दायरे में बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां शौचालय की सुविधा, पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर और अन्य आवश्यक व्यवस्था की गई है। उन्होंने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचने का अनुरोध किया। इसके अलावा वहां राहत किट भी बांटी जा रही हैं। अधिकारी की टिप्पणी की सोशल मीडिया पर आलोचना हुई लेकिन राज्य सरकार की ओर से अधिकारी के व्यवहार के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है।

मॉस्को से आ रही फ्लाइट में बम की सूचना, आनन-फानन में दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारे गए यात्री

नई दिल्ली (आरएनएस)। मॉस्को से दिल्ली आ रही फ्लाइट में शुक्रवार अल-सुबह बम रखे होने की सूचना मिली। सुचना मिलने के बाद ही अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट तडक़े 3.20 बजे लैंड हुई। आनन-फानन में सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को नीचे उतारा गया। इसके बाद फ्लाइट की जांच की गई। फ्लाइट में 386 यात्री और 16 क्रू मेंबर्स थे।

जानकारी के अनुसार अधिकारियों को अब तक विमान में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले को लेकर छानबीन शुरू कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के कंट्रोल रूम की सोशल मीडिया साइट पर गुरुवार देर रात 11 बजे रूस से आ रहे विमान में बम की सूचना मिली थी। हालांकि, पुलिस का कहना है कि फ्लाइट में बम होने की जानकारी सीआईएसएफ को ईमेल के जरिए मिली।

इससे पहले पिछले हफ्ते ही डीजीसीए को ईरान से चीन जा रही एक फ्लाइट में भी बम होने की सूचना मिली थी। तब भारत की तरफ से एहतियात बरतते हुए ईरान की महान एयर की इस फ्लाइट को जयपुर में लैंड करने की पेशकश की गई थी। वायुसेना ने फ्लाइट को लैंड कराने के लिए सुखोई लड़ाकू विमान भी भेजे थे। हालांकि, बाद में इस फ्लाइट में बम की सूचना झूठी साबित हुई थी।

ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच नहीं होगी, कोर्ट ने खारिज की मांग

वाराणसी (आरएनएस)। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले पर सुनवाई की। जिला जज ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दाखिल करने और उस पर बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित कर लिया था।

अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये एक फव्वारा है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने इसे सील करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने केस जिला जज को ट्रांसफर कर इस वाद की पोषणीयता पर नियमित सुनवाई कर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। जिला जज ने पूजा की मांग वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना था।

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र ने कहा, 'चुनावी बांड' काला धन नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को राजनीतिक दलों को चंदा देने का पारदर्शी तरीका बताते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इसमें काले धन की कोई संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरथना की पीठ के समक्ष एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीति दलों के चंदे के लिए धन प्राप्त करने की बिल्कुल पारदर्शी पद्धति है।

मेहता ने पीठ के समक्ष कहा, अब कुछ भी काला नहीं है, बल्कि सब कुछ पारदर्शी है। इस पर पीठ ने सॉलीसीटर जनरल से पूछा कि क्या सिस्टम ने जानकारी दी है कि पैसा कहां से आ रहा है। मेहता ने जवाब दिया, बिल्कुल। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए इस मामले को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इसकी सुनवाई एक बड़ी पीठ कर सकती है। इस पर पीठ ने कहा कि जब तक विचारों का टकराव नहीं होता है, तब तक मामले को बड़ी पीठ के समक्ष नहीं भेजा जा सकता है।

एनजीओ की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने चुनाव में विदेशी धन के इस्तेमाल पर भी चिंता व्यक्ति और कहा कि याचिका में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जो लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। इनमें चुनावी बांड की शुरुआत और राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाना शामिल है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने राज्यों में आने वाले महीनों में चुनाव होने का हवाला देते हुए मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और अन्य ने 2 जनवरी, 2018 को शुरू की गई केंद्र की चुनावी बांड योजना की वैधता को चुनौती दी है। याचिकाओं में राजनीतिक फंडिंग के स्रोत पर सवाल उठाए गए हैं। शीर्ष अदालत ने 27 मार्च 2021 को एक आदेश द्वारा इस आरोप को खारिज कर दिया था कि योजना पूरी तरह से अपारदर्शी थी। यह आशंका कि विदेशी कॉरपोरेट घराने बांड खरीद सकते हैं और देश में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, 'गलत धारणा' थी।

दूसरे दिन भी खनिज शाखा में दस्तावेज खंगाल रही ईडी की टीम

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिला गठन के 23 वर्ष के बाद ऐसा पहला मौका है जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने कलेक्टर कार्यालय में संचालित खनिज शाखा में दबिश दी। उसकी कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। ईडी के अधिकारी जिला खनिज। न्यास और खनिज शाखा में दस्तावेजों को उलटने पलटने से लेकर तथ्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां से क्या कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली, इसका खुलासा आने वाले दिनों में ईडी की ओर से किया जाएगा। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की टीम सीआरपीएफ के साथ 1 दिन पहले दोपहर में कलेक्टोरेट पहुंची थी।

खनिज संसाधन और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड्स की उपयोगिता से संबंधित शिकायत को लेकर इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहां जांच कर रही है। जांच को लेकर माना जा रहा है कि पूर्व में हुई गड़बडिय़ों और मनमानी को लेकर यह सब उठापटक चल रही है। कुछ महीने पहले पूर्व कलेक्टर रानू साहू के कार्यकाल के दौरान हुए कुछ कार्यों से संबंधित मामलों की शिकायत भारत सरकार से हुई थी और इसकी व्यापक चर्चा हुई थी। संभवत सरकार ने इस पर संज्ञान लेने के साथ अगली कार्रवाई के निर्देश दिए। उक्तानुसार मामले की गहराई से जांच करने और सच को बाहर लाने के लिए इंफोर्समेंट की टीम लगाई गई है। मामला काफी गंभीर हो सकता है, इसका पता इस बात से चलता है कि ईडी की टीम गुरुवार से यहां पर है जो आज दूसरे दिन भी माइनिंग एवं इससे संबंधित माइनिंग फंड से जुड़ी फाइलों के पन्ने पलटने में गतिशील है। अब तक कार्रवाई से संबंधित किसी प्रकार का ब्यावरा सार्वजनिक नहीं हुआ है। प्रशासनिक कार्यालय में ईडी की उपस्थिति से अजीब माहौल बना हुआ है। अभी भी मुख्य द्वार केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। लेकिन गुरुवार और आज के वातावरण में काफी अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। जिले में अगली बारी किसकी, अब यह चर्चा इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट्स के द्वारा कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू के रायगढ़ स्थित सरकारी बंगले को सील करने के साथ कोरबा के 3 बड़े कारोबारियों के ठिकाने पर ईडी ने दबिश देने के साथ कई दस्तावेज जप्त कर लिए। जबकि अगले दिवस कलेक्ट्रेट में ईडी की दबिश हुई। इस कार्रवाई ने अब कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सरकारी कार्यालयों से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अब इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि अब ईडी के निशाने पर कौन सा डिपार्टमेंट या औद्योगिक समूह हो सकता है।

बेटी की मौत की खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ने से पिता का निधन

चेन्नई (आरएनएस)। चेन्नई के सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे एक स्टॉकर द्वारा धक्का दिए जाने के बाद मारी गई 20 वर्षीय सत्यप्रिया के पिता को बेटी की मौत की खबर सुनकर दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। मनिकम (56) की गुरुवार देर रात चेन्नई के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत के बारे में जानने के बाद उनको गहरा धक्का लगा जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने इस बीच शुक्रवार सुबह आरोपी सतीश (23) को गिरफ्तार कर लिया, जिसने गुरुवार को सत्यप्रिया को चलती ट्रेन के आगे धकेल दिया था। वह जघन्य अपराध करने के बाद से फरार था और हालांकि उसे पकडऩे की कोशिश की थी, लेकिन वह भागने में सफल रहा था।

पीडि़ता की मां चेन्नई के आदमबक्कम पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल हैं। सत्यप्रिया जैन कॉलेज, चेन्नई में पढ़ती थी और क्साल के लिए जा रही थी, जब अचानक सतीश मौके पर पहुंचा और दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सतीश ने उसे चलती ट्रेन के सामने धकेल दिया, जो एग्मोर से तांबरम की ओर जा रही थी।

सेंट थॉमस माउंट पुलिस स्टेशन की पुलिस ने कहा कि, सतीश जो आठवीं कक्षा में ड्रॉप आउट था, एक सेवानिवृत्त पुलिस सब-इंस्पेक्टर का बेटा था और पिछले कुछ सालों से सत्यप्रिया का पीछा कर रहा था। पिछले हफ्ते लडक़ी ने उसके खिलाफ स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

केदारनाथ में रोपवे बनाने को मंजूरी, सिर्फ 30 मिनट में पूरी होगी यात्रा; 1000 करोड़ रुपए होंगे खर्च

देहरादून (आरएनएस)। केदारनाथ के लिए रोपवे का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। परियोजना पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। रोपवे बन जाने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या बढऩे की उम्मीद की जा रही है।

प्रमुख सचिव, वन एवं लोनिवि, आरके सुधांशु ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने केदारनाथ सेंक्चुरी एरिया में रोपवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। साथ ही केदारनाथ के पैदल ट्रैक व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को भी बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। इन परियोजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। इस परियोजना में कुल 26 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।

केदारनाथ के लिए रोपवे बन जाने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा पांच हजार यात्रियों को ले जाने की होगी। साथ ही राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़चट्टी तक साढ़े पांच किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। यह मार्ग 2013 की आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

हेमकुंड साहिब रोपवे को भी हरी झंडी राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने सेंचुरी क्षेत्र नहीं होने के कारण हेमकुंड रोपवे परियोजना को मंजूरी को जरूरी नहीं माना। ऐसे में अब इस परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है।

चार बंधक श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ रवाना हुई रेस्क्यू टीम

तमिलनाडु करूर जिले में बंधक बनाएं गए थे कबीरधाम जिले के मजदूर

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के चार श्रमिकों को बंधक से मुक्त करने उन्हे सकुशल वापस लाने के लिए रेस्क्यू टीम तमिलनाडु पहुंची गई है। रेस्क्यू टीम ने तमिलनाडु के करूर जिले में बंधक बनाए गए श्रमिकों को हाल-चाल जाना और स्थानीय जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू टीम सभी श्रमिकों को मुक्त कराने में सफल भी रही। रैस्क्यू टीम सभी श्रमिकों को सकुशल अपने साथ छत्तीसगढ़ रवाना हो गई है। इधर कबीरधाम कलेक्टर जनमेजय महोबे भी लगातार स्थानीय करूर जिले के कलेक्टर से संपर्क बनाए रहे और रेस्क्यू टीम को उनका लगातार मदद भी मिली।

वनांचल क्षेत्र, पंडरिया विकासखंड के ग्राम पंचायत अमानिया के आश्रित गांव अमलीटोला के 4 युवा बैगा के तमिलनाडु राज्य में ठेकेदार द्वारा बंधुआ मजदूर बनाए जाने की जानकारी मिलने पर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान में लिया और 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित की। राजस्व, श्रम, बाल संरक्षण, और पुलिस विभाग की गठित संयुक्त टीम तमिलनाडु के कुरूर जिले से 4 बंधक श्रमिको को मुक्त कर छत्तीसगढ़ सकुशल घर वापसी हो रही है।

उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर को थाना कुकदूर में करन सिंह बैगा के पिता रूपसिंह बैगा के द्वारा शिकायत की गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए 06 अक्टूबर को पुष्टि किए जाने के उपरांत 6 अक्टूबर को कलेक्टर जनमेजय महोबे ने करूर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, श्रमायुक्त को तथ्य की गंभीरता से अवगत कराया एवं तत्काल कार्यवाही करने के लिए पत्र प्रेषित किया। 7 अक्टूबर को बंधक श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए जिला स्तर पर 5 सदस्यीय टीम जिसमें नायब तहसीलदार, श्रम निरीक्षक, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक को रवाना किया गया। टीम पहुंचने पर एवं कलेक्टर जनमेजय महोबे के पत्रों पर करूर कलेक्टर ने ई.सी.सी. फैक्ट्री में उच्च स्तरीय जांच कराई। जांच में जिले के नौजवान बंधक पाए गए जिन्हे छुडाया गया एवं बंधक विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया। केन्द्र सरकार के प्रावधानों के तहत विमुक्ति प्रमाण पत्र के साथ तत्काल सहायता राशि 30 हजार रूपए प्रति बंधक के मान से दी जाती है, इसके लिए भी कलेक्टर महोबे ने पुन: करूर कलेक्टर, तमिलनाडु को नियमों के तहत राशि दिलाने के लिए पत्र जारी किया गया एवं वे स्वयं कलेक्टर करूर के साथ संपर्क में थे जिससे इस कार्यवाही में करूर कलेक्टर का काफी सहयोग रहा। कलेक्टर महोबे के द्वारा उनके खाने-पीने एवं स्वास्थ्य के बारे में लगातार जानकारी लेते रहे तथा 2 बैगा श्रमिक जगत सिंह बैगा एवं करन सिंह बैगा की हालत खराब होने पर उनके स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए पत्र लिखा तथा 11 अक्टूबर को रात्रि 11 बजे दोनो श्रमिकों को करूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उन्हे इलाज उपरांत फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हुआ। जिला श्रम पदाधिकारी शोएब काजी ने बताया कि कलेक्टर जनमेजय महोबे की पहल पर 4 श्रमिकों के खाते करूर में खुलवाये गए तथा बहुत जल्द वे सकुशल जिला स्तरीय टीम के साथ वापस आ रहे है।